विवरण

1996-97 और 1997-98 के दौरान खाद्यान्न, दलहन तथा तिलहनों के उत्पादन का राज्य-वार अनुमान उत्पादन (हजार टन)

राज्य	खाद्यान्न		दलहन		तिलहन	
	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98
आंध्र प्रदेश	12684	10421	768	562	2420	1447
असम	3532	3804	68	73	155	172
बिहार	14134	13289	613	666	161	143
गुजरात	5209	5700	663	781	3809	4056
हरियाणा	11455	10980	343	440	1004	866
हिमाचल प्रदेश	1289	1409	11	33	10	11
जम्मू व कश्मीर	1324	1644	17	22	44	42
कर्नाटक	9271	8638	669	485	1714	1380
केरल	858	1151	15	19	11	17
मध्य प्रदेश	19563	18813	3715	3376	1998	6041
महाराष्ट्र	14590	10172	2037	1381	2384	1971
उड़ीसा	4834	6871	299	384	177	180
पंजाब	21564	21649	81	97	310	303
राजस्थान	12838	12925	1876	1908	3525	3222
तमिलनाडु	7645	8761	410	391	1929	1468
उत्तर प्रदेश	42693	42001	2664	2231	1772	1668
पश्चिम बंगाल	13739	13803	156	173	451	619
अन्य	2099	2096	54	53	82	83
समस्त भारत	199321	194127	14460	13075	24960	23689

गन्ना उत्पादक क्षेत्र

2441. **श्री रामगोपाल यादव:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन प्रदेशों में गन्ने का उत्पादन अधिक होता है;

(ख) इन राज्यों में गन्ना उत्पादक क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है;

(ग) क्या गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहित करने और समय पर गन्ने की पिराई को सुनिश्चित करने के लिए उक्त राज्यों में गन्ना मिलों की स्थापना करने हेतु सुविधाएं प्रदान की जाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) वर्ष 1997-98 के दौरान मुख्य गन्ना उत्पादक राज्यों में गन्ने के क्षेत्र को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है **(नीचे देखिये)**।

(ग) और (घ) चीनी के नए कारखानों को लाइसेंस प्रदान करने और विद्यमान चीनी कारखानों के विस्तार संबंधी दिशा निर्देशों में प्रति दिवस न्यूनतम पिराई क्षमता, मिलों द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकियों के अपनाने, प्रस्तावित और विद्यमान गन्ना मिलों के बीच रखी जाने वाली कम से कम दूरी, ईख (गन्ना) की उपलब्धता और/अथवा क्षेत्र में गन्ने के विकास की सम्भावना, उत्पादक सहकारी समितियों को तरजीह आदि का ध्यान रखा जाता है। इन उपायों से गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलेगा और गन्ने की समय पर पिराई सुनिश्चित होगी।

विवरण

गन्ने के क्षेत्र का राज्य-वार प्राक्कलन, 1997-98

राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)
1	2
आंध्र प्रदेश	192.0
बिहार	170.0
गुजरात	155.0
हरियाणा	140.0
कर्नाटक	241.0
महाराष्ट्र	460.0
पंजाब	132.0
तमिलनाडु	293.0
उत्तर प्रदेश	1956.0
अन्य	178.0
समस्त भारत	3917.0

दिल्ली दुग्ध योजना को दिया जाने वाला वार्षिक अनुदान

2442. श्री रामगोपाल यादव:
श्री ईश दत्त यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना को प्रतिवर्ष कितना अनुदान प्रदान किया जाता है और उक्त योजना द्वारा उसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकारियों की मिली भगत् से दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने दूध की कालाबाजारी को रोकने और इस संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए अब तक कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है और दूध की कालाबाजारी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के लोगों को सस्ते मूल्य पर दूध उपलब्ध कराने की योजना को किस प्रकार सफल बनाया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) दिल्ली दुग्ध योजना को केन्द्र सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई बजटीय सहायता इस प्रकार है:—

वर्ष	बजटीय सहायता (लाख रुपए में)
1995-96	4,514.31
1996-97	4,967.60
1997-98	5,847.60

बजटीय सहायता का उपयोग राजस्व प्राप्तियों तथा उस खर्च के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए किया जाता है जो दूध की उत्पादन लागत तथा बिक्री मूल्य के अंतर के कारण है।

(ख) से (घ) दिल्ली दुग्ध योजना, दूध को अन्य आपूर्तिकताओं की तुलना में काफी कम मूल्य पर बेच रही है। इसके परिणामस्वरूप, दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध बूथों पर इसकी भारी मांग है। कालाबाजारी से संबंधित शिकायतों पर ध्यान दिया जा रहा है तथा उनके सही पाए जाने पर वरिष्ठ डिपो एजेंट/डिपो एजेंट/ लाभार्थियों आदि की एजेंसियों को रद्द करने सहित कार्रवाई की जाती है। उपभोक्ता सलाहकार समिति तथा रेजीडेंट वैलफेयर एसोसिएशन भी वितरण तंत्र के साथ तेजी से जुड़ रही है ताकि इसे न्यायसंगत बनाया जा सके।

Production of Cocoa in the country

2443. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the total production of cocoa in the country during each of the last three years till May 1998, State-wise;

(b) whether Government have conducted any study/research for increasing the production of cocoa in the country, particularly in the State of Orissa; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) The details are given in the enclosed Statement. (*See* below).